भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1531
दिनांक 15 **दिसंबर**, 2022

रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव

†1531.**श्री राहुल रमेश शेवाले** :
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:
श्री चंद्र शेखर साहू:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रूस-यूक्रेन युद्ध का वैश्विक ऊर्जा प्रणाली पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है और इससे आपूर्ति और मांग के पैटर्न में बाधा उत्पन्न हुई है तथा दीर्घकालिक व्यापारिक संबंध टूट गए हैं;
(ख) यदि हां, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर रूस-यूक्रेन युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा है;
(ग) क्या ऊर्जा क्षेत्र में भारत-अमरीकी सहयोग की अपार संभावनाएं है;
(घ) यदि हां, तो इस क्षमता का दोहन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ड.) क्या दोनों देश ऊर्जा संबंधी मुद्दों के लिए एक हरित गलियारा बनाने पर सहमत है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क) और (ख): सरकार द्वारा नियमित आधार पर वैश्विक आर्थिक विकासों पर निगरानी रखी जाती है और सतत आधार पर आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

रूस और यूक्रेन के बीच भू-राजनैतिक स्थिति के चलते वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस के मूल्यों में भारी अस्थिरता पाई गई है। चूंकि भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का 85% आयात करता है, सरकार अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों के साथ-साथ भू-राजनैतिक स्थिति से उत्पन्न संभावित ऊर्जा आपूर्ति व्यवधानों पर बारीकी से नज़र रख रही है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा हित में यथा अपेक्षित कदम उठा रही है।

(ग) से (च): भारत और अमरीका के बीच ऊर्जा सहयोग के लिए 'अमरीका-भारत कार्यनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी (यूएसआईएससीईपी)' पहले से ही मौजूद है। यूएसआईएससीईपी कार्यढांचा (फ्रेमवर्क) के माध्यम से, भारत और अमरीका दोनों देशों के पणधारकों के बीच स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे उभरती प्रौद्योगिकियों सहित स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने में सुविधा हो रही है।

दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 को हुई यूएसआईएससीईपी की पिछली मंत्रालयी बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, "दोनों राष्ट्र ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को विकसित करने पर सहमत हो गए हैं जिसमें वाणिज्यिक सहयोग के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने में सरकारी सहायता से दोनों देशों के उद्यमियों को एक साथ ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर ध्यान देना होगा"।

****